GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.122

TO BE ANSWERED ON 30/07/2021

PRODUCTION OF OILSEEDS AND EDIBLE OIL IN THE COUNTRY

*122. Dr. BANDA PRAKASH:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether any concrete steps are being taken by Government for increasing the production of oilseeds and edible oil to avoid the need for import of edible oil;

(b) if so, the details thereof and the steps being taken by Government for promoting farming/cultivation of oilseeds among farmers so that there is no need of importing edible oil;

(c) whether Government has held National Seeds Conferences during the last three years to help the farmers during their sowing season in view of the changing circumstances in the country; and

(d) if so, the details and outcome thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY):

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN RESPECT OF PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 122 FOR 30.07.2021 REGARDING "PRODUCTION OF OILSEEDS AND EDIBLE OIL IN THE COUNTRY"

(a) & (b): Yes, Sir. The Government is implementingthe National Food Security Mission (Oilseeds & Oil Palm) in the country to increase the production and productivity of oilseeds and oil palm and thereby increasing the production of domestic edible oils. The scheme is being implemented with an objective to augment the availability of edible oils and to reduce the import by increasing the production and productivity of oilseeds crops *viz.*, Soybean, Groundnut, Rapeseed-Mustard, Sunflower, Castor, Sesame, Safflower, Linseed and Niger and also for oil palm.The production of oilseeds has gone up from 186.00 lakh tonnes during 1991-92 to 365.65 lakh tonnes during 2020-21 (3rd Advance Estimates). The area under Oilpalm cultivation has increased from 8585 ha in 1991-92 to 3.70 lakh ha in 2020-21.

For NFSM (oilseeds), interventions such as purchase of breeder seeds, production of foundation and certified seeds, distribution of certified seeds, plant protection equipments and chemicals, distribution of Gypsum/pyrite/lime/single super phosphate, Nuclear Poly Hydrosis Virus, Supply of improved farm implements, distribution of sprinkler sets, pipes for carrying water from source to the field, integrated pest management, famers, officer's and extension worker's training are undertaken.Newly released high yielding varieties of oilseeds are also distributed through the oilseeds minikit programmes to the farmers free of cost.Further transfer of technology through Front Line Demonstrations (FLDs) and Cluster Front Line Demonstrations (CFLDs) are also being provided to the farmers through the Indian Council of Agricultural Research (ICAR)/ Krishi Vigyan Kendra (KVKs).

The interventions under NFSM-Oil palm comprises of three major components i.e (i) area expansion inputs covering assistance for planting material, maintenance/cultivation cost, inputs for inter-cropping during gestation period of 4 years, (ii) production inputs covering drip-

irrigation, bore-well/water harvesting structure, diesel/electric pump set, vermi-compost unit, establishment of new seed garden, machinery &harvesting tools, special component for NE/hilly states/ left wing (LW) areas for construction of roads and establishment of new oil palm processing unit and (iii) transfer of technologies covering assistance for training of farmers/officers, demonstrations on oil palm at farmer's field, need based Research & Development projects on oil palm, including import of germplasm and training infrastructure support to Indian Council of Agricultural Research system.

To increase production and productivity of oilseeds, the annual action plan for 3 years (2021-22 to 2023-24) for Central Seed Agencies has been approved for purchase of Breeder seeds and production of Foundation and Certified seeds.

During the Rabi 2020-21, a special programme on Rapeseed &Mustard was implemented as a result of which the production has reached to 99.80 lakh tonnes in 2020-21 (3rd advance estimate) from 91.23 lakh tonnes of 2019-20. Further, for Kharif 2021, a total of 922935 number of oilseed minikits of high yielding varieties of soybean, groundnut and sesame have been allocated for distribution in all the major oilseed growing states. The details are as under;

S. No.	Oilseeds Crop	States and Districts	No of Minikits
1.	Groundnut	7 States & 53 districts	74000
2	Soybean	9 states & 90 districts	816435
3	Sesame	9 states & 50 districts	32500
	Total	-	**922935**

Due to the above major initiatives, production of oilseeds & edible oils has increased from 314.59 lakh tonnes (2017-18) to 365.65 lakh tonnes (2020-21) and from 103.80 lakh tonnes (2017-18) to 110.00 lakh tonnes (2020-21) respectively, where as the import of edible oils has decreased from 154.00 lakh tonnes in 2017-18 to 133.70 lakh tonnes in 2020-21.

(c) & (d): The Government of India supplements the efforts of the State Governments by coordinating seed requirement and availability among the states through Zonal Seed Review Meetings held before every crop season. The crop-wise requirement and availability of Certified/quality oilseeds in the country during from the year 2018-19 to Kharif-2021 is as under:

Qty. in Lakh Quintals

Crop	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**Kharif 2021**	
	R	**A**	**R**	**A**	**R**	**A**	**R**	**A**
Groundnut	25.54	29.27	21.33	25.52	26.35	26.70	19.86	21.70
Rapeseed & Mustard	2.34	2.99	2.47	2.84	2.88	3.08	0.00	0.00
Til	0.49	0.56	0.39	0.41	0.50	0.53	0.20	0.24
Sunflower	0.28	0.43	0.17	0.19	0.33	0.39	0.14	0.14
Soyabean	29.11	28.17	30.52	33.88	27.23	24.03	28.99	28.11
Linseed	0.14	0.11	0.19	0.13	0.13	0.16	0.01	0.01
Castor	0.56	0.62	0.44	0.53	0.52	0.58	0.50	0.91
Safflower	0.06	0.1	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
Niger/Others	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04		
Oilseed Total	**58.56**	**62.28**	**55.61**	**63.60**	**58.03**	**55.56**	**49.73**	**51.15**

R - Requirement A - Availability

******

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 122
30 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: देश में तिलहन और खाद्य तेल का उत्पादन

***122 डा. प्रकाश बांडा :**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य तेल के आयात की आवश्यकता से बचने के लिए तिलहन और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों को तिलहन की खेती/कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खाद्य तेल के आयात की कोई आवश्यकता न पड़े;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में बदलती परिस्थितियों के मद्देनज़र बुआई मौसम के दौरान किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बीज सम्मेलन आयोजित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कैलाश चौधरी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

देश में तिलहन और खाद्य तेल के उत्पादन के संबंध में दिनांक 30.07.2021 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): जी,हाँ। सरकार तिलहन और ऑइल पाम के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने और उसके द्वारा घरेलू खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ऑइल पाम) कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सूरजमुखी, अरंडी, तिल, कुसुम, अलसी तथा नाइजर और पाम ऑइल का भी उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाकर आयात को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। तिलहन का उत्पादन 1991-92 के दौरान 186.00 लाख टन से बढ़कर 2020-21 (तीसरा अग्रिम अनुमान) के दौरान 365.65 लाख टन हो गया है। ऑइल पाम की खेती का क्षेत्र 1991-92 में 8585 हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में 3.70 लाख हेक्टेयर हो गया है।

एनएफएसएम (ऑइलसीड्स) के लिए, प्रजनक बीजों की खरीद, मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों, पौध संरक्षण उपकरणों और रसायनों का वितरण, जिप्सम/पाइराइट/ लाइम/सिंगल सुपर फॉस्फेट, न्यूक्लियर पॉली हाइड्रोसिस वायरस का वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, स्प्रिंकलर सेटों, स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइपों का वितरण, एकीकृत कीट प्रबंधन, किसानों, अधिकारियों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण जैसे प्रयास किए जाते हैं। तिलहन की नई जारी उच्च उपज वाली किस्मों को भी तिलहन मिनीकिट कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को निशुल्क वितरित किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से किसानों को फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन्स (एफएलडी) और क्लस्टर फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन्स (सीएफएलडी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी का आगे हस्तांतरण भी किया जा रहा है।

एनएफएसएम-ऑइल पाम के अंतर्गत हस्तक्षेपों में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं यथा - (i) क्षेत्र विस्तार आदानों जिसमें रोपण सामग्री, रखरखाव/खेती की लागत, 4 साल की परिपोषण अवधि के दौरान अंतर-फसल के लिए आदानों हेतु सहायता शामिल है, (ii) उत्पादन आदान जिसमें ड्रिप-सिंचाई, बोर-वेल/जल संचयन संरचना, डीजल/विद्युत पंप सेट, वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट, नए बीज उद्यान की स्थापना, मशीनरी और कटाई के उपकरण, पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों/वामपंथी (एलडब्ल्यू) क्षेत्रों के लिए सड़कों के निर्माण और नई ऑइल पाम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए विशेष घटक शामिल है और (iii) प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण जिसमें किसानों/अधिकारियों के प्रशिक्षण, किसान के खेत में ऑइल पाम पर निदर्शन, जर्मप्लाज्म के आयात सहित ऑइल पाम पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता तथा भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली परिषद को प्रशिक्षण अवसंरचना सहायता शामिल है।

तिलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रजनक बीजों की खरीद तथा मूल एवं प्रमाणित बीजों की के उत्पादन हेतु केंद्रीय बीज एजेंसी के लिए 3 वर्ष (2021-22 से 2023-24) की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई है ।

रबी 2020-21 के दौरान, रेपसीड और सरसों पर एक विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 2019-20 के 91.23 लाख टन से बढ़कर 2020-21 (तृतीय अग्रिम अनुमान) में 99.80 लाख टन तक पहुंच गया है। खरीफ 2021 के लिए सोयाबीन, मूंगफली और तिल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कुल 922935 तिलहन मिनीकिट सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं । विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्यक्रम	राज्यों एवं जिलों की संख्या	मिनीकिटों की संख्या
1	मूंगफली	7 राज्य और 53 जिले।	74000
2	सोयाबीन	9 राज्य और 90 जिले।	816435
3	तिल	9 राज्य और 50 जिले	32500
	कुल	-	**922935**

उपरोक्त प्रमुख पहलों के कारण, तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन 314.59 लाख टन (2017-18) से बढ़कर क्रमशः 365.65 लाख टन (2020-21) और 103.80 लाख टन (2017-18) से बढ़कर 110.00 लाख टन (2020-21) हो गया है, जबकि खाद्य तेलों का आयात वर्ष 2017-18 के 154.00 लाख टन से घटकर 2020-21 में 133.70 लाख टन हो गया है।

(ग) एवं (घ): भारत सरकार प्रत्येक फसल मौसम से पहले आयोजित क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों के बीच बीज की आवश्यकता और उपलब्धता के समन्वय के साथ सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है । वर्ष 2018-19 से खरीफ-2021 के दौरान देश में प्रमाणित/गुणवत्ता वाले फसल-वार बीजों की आवश्यकता एवं उपलब्धता निम्नानुसार है:

मात्रा, लाख क्विंटल में

फसल	2018-19		2019-20		2020-21		खरीफ 2021	
	आर	ए	आर	ए	आर	ए	आर	ए
मूंगफली	25.54	29.27	21.33	25.52	26.35	26.70	19.86	21.70
रेपसीड/सरसों	2.34	2.99	2.47	2.84	2.88	3.08	0.00	0.00
तिल	0.49	0.56	0.39	0.41	0.50	0.53	0.20	0.24
सूरजमुखी	0.28	0.43	0.17	0.19	0.33	0.39	0.14	0.14
सोयाबीन	29.11	28.17	30.52	33.88	27.23	24.03	28.99	28.11
अलसी का बीज	0.14	0.11	0.19	0.13	0.13	0.16	0.01	0.01
अरंडी	0.56	0.62	0.44	0.53	0.52	0.58	0.50	0.91
कुसुम	0.06	0.1	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
नाइजर/अन्य	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04		
कुल तिलहन	**58.56**	**62.28**	**55.61**	**63.60**	**58.03**	**55.56**	**49.73**	**51.15**

आर - आवश्यकता ए - उपलब्धता

*****

DR. BANDA PRAKASH: Sir, what is the action plan of the Government of India to achieve self-sufficiency in the edible oils? ...*(Interruptions)*... What is the extent of acreage that they are going to extend? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने खाद्य तेल की आपूर्ति की योजना के बारे में पूछा है। ...(**व्यवधान**)... भारत सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं, जिससे हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए National Food Security Mission के तहत National Food Security Mission - Oilseeds, National Food Security Mission - Oil Palm और National Food Security Mission - Vriksha Janit Tilhan को लेकर सरकार काम कर रही है। ...(**व्यवधान**)... इन दो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वह किसानों को सहायता भी प्रदान कर रही है और सहयोग भी कर रही है। ...(**व्यवधान**)... साथ ही साथ इसके लिए उन्नत किस्म के बीज किसानों को दिए जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)... किसानों को seed mini kit भी वितरित की जाती है।...(**व्यवधान**)... Inter-cropping management के माध्यम से diversification पर जाने के लिए भी किसानों को जाग्रत किया जाता है।...(**व्यवधान**)... हमने लगभग 36 seed hubs तैयार किए हैं, जहां हर किस्म के सीड्स तैयार करके किसानों को दिए जाते हैं, ताकि किसानों का उत्पादन अधिक हो सके।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप में जवाब दें।...(**व्यवधान**)...

DR. BANDA PRAKASH: Sir, they are spending around Rs. 65,000-70,000 crores on the import of edible oil but they are allocating only Rs. 400-500 crores on seed farming. ...*(Interruptions)*... Is there any plan with the Government of India to increase the Budget allocation for more cultivation of oil seed farming? ...*(Interruptions)*...

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, एक मिशन के तहत इस काम को किया जा रहा है।...(**व्यवधान**)... हमारे यहां तेल उत्पादन कैसे बढ़े सके, इस दृष्टि से किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है।...(**व्यवधान**)... जैसा हमने बताया, National Food Security Mission के तहत इसके लिए अलग से बजट allocate किया जा चुका है, जिससे हम किसानों को motivate कर सकें और processing के लिए सहायता भी दे सकें।...(**व्यवधान**)... इसमें हम राज्य सरकारों को भी सहायता देते हैं, ताकि वे भी इस काम में और अधिक आगे बढ़ सकें।...(**व्यवधान**)...

श्री महेश पोद्दार : महोदय, 20 जुलाई को लोक सभा में स्टार्ड क्वेश्चन का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि देश को ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे देश में 36 oilseed hubs बना करके एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है।...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या झारखंड समेत अन्य जगहों पर ऐसे और hubs बनाने की सरकार की कोई योजना है, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें? ...(**व्यवधान**)...

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या और स्थानों पर भी ऐसे hubs स्थापित किए जाएंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसमें वहां के वातावरण के गुण-अवगुण और वहां की प्रोडक्शन की स्थिति को देखा जाता है। ...(**व्यवधान**)... साइंटिस्ट्स की रिसर्च के आधार पर टीम गठित करते हुए इसका निर्णय लिया जाता है।...(**व्यवधान**)... अगर टीम को लगता है कि वहां पर वास्तव में उत्पादन हो सकता है, तो वहां seed hub बनाकर...(**व्यवधान**)... निश्चित रूप से हम सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं।...(**व्यवधान**)... मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई स्थान होगा, तो वहां किसानों के सहयोग के लिए मोदी जी की सरकार हर समय तैयार है।...(**व्यवधान**)... चाहे seed hub बनाने की बात है, चाहे तेल के उत्पादन की बात हो या processing की बात हो।...(**व्यवधान**)... अगर इसके लिए कहीं से भी agriculture infrastructure को शोधित करना होता है, तो हमारी सरकार वह काम निश्चित रूप से करती है।...(**व्यवधान**)... आवश्यकता के अनुसार, वहां के गुण-अवगुण और व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार हर सम्भव मदद करती है।...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों के दौरान क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी को दोगुना करने और उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? ...(**व्यवधान**)... यदि हां, तो क्या जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए भी कोई योजना बनाई गई है? ...(**व्यवधान**)...

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने किसानों की इनकम डबल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।...(**व्यवधान**)... इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज देने की भी योजना बनाई गई है।...(**व्यवधान**)... साथ ही Agriculture Infrastructure Fund के माध्यम से भी उन्हें सहायता दी जाती है।...(**व्यवधान**)... MSP को भी डेढ़ गुना कर दिया गया है।...(**व्यवधान**)... इस तरह से किसानों की income double करने के लिए एक प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

माननीय सदस्य ने organic farming की बात पूछी है, तो organic farming के लिए अगर किसान cluster बना कर खेती करते हैं,...(**व्यवधान**)... अगर 10 किसान मिल कर 20 हेक्टेयर जमीन के ऊपर खेती करते हैं, तो उसमें लगभग 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।...(**व्यवधान**)... इसमें से 21,000 रुपये direct benefit के तौर पर किसान के खाते में डाले जाते हैं।...(**व्यवधान**)... साथ ही खेती के लिए bio-fertilizer तैयार करने के लिए भी सरकार ने subsidy देने का प्रावधान किया है और किसानों की सहायता की है।...(**व्यवधान**)... किसान जब भी organic खेती करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा।...(**व्यवधान**)... इस दृष्टि से भारत सरकार ने अलग से भी बजट का प्रावधान किया है।...(**व्यवधान**)... भारत सरकार की जो 'नमामि गंगे योजना' चल रही है, उसके तहत गंगा के किनारे-किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।...(**व्यवधान**)... इस तरह से सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.30 p.m.